

मुख्यमंत्री ने बीसलपुर व नवनेरा बाँध भरने पर खुशी जताई

उन्होंने कहा कि मानसून में अच्छी बारिश से नियमित जलपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी

जयपुर, 24 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बीसलपुर बांध का पूरा भरना अत्यंत हर्ष का विषय है। यह पहली बार है जब जुलाई माह में बीसलपुर बांध का गेट खोला गया है। उन्होंने कहा कि राम जल सेतु लिंक

और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

उल्लेखनीय है कि 24 जुलाई 2025 की तारीख ने प्रदेश में नया इतिहास रचा है। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पहली बार लगातार दो साल बीसलपुर बाँध पूरा भरा है। इस बाँध से जयपुर, अजमेर व टोंक जिले की करीब एक करोड़ की आबादी को पेयजल आपूर्ति की जाती है।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

पूरा भर गया। इसमें पानी का लेवल 214 आरएल मीटर पहुंच गया जिसके बाद इसके गेट नंबर 11, 12 व 13 खोल दिए गए। इससे 600 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इस निकासी से अपस्ट्रीम में कालीसिंह नदी

कल तक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यादव, तेजस्वी यादव और अन्य नेता, इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। सभी को लग रहा है कि मतदाताओं को बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करना और इस तरह चुनाव को चुराना, लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसके बाद से फोकस लगावार बिहार और एस आई आर मुद्दे पर बना हुआ है।

विपक्ष रोजाना संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहा है और कल वे गांधी प्रतिमा से संसद के मकर द्वार तक मार्च करेंगे।

सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि विपक्ष को आपत्ति है, तो वह चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट जाए।

अब यह विपक्ष पर निर्भर है कि वह लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेगा और उन तरीकों का विरोध कैसे करेगा, जिनके जरिए संविधान की अनदेखी करके, दिन-दहाड़े चुनावों में सेंध लगाई जा रही है तथा उन्हें प्रभावित किया जा रहा है।

आज निर्णय होगा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अंतरिम रोज़े जारी रहनी चाहिए? पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति क्रांत ने कहा , हम कल 10-15 मिनट और लेंगे और मामले का निपटारा कर देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने मुम्बई ट्रेन धमाकों पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

नयी दिल्ली, 24 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में दोषी सभी 12 लोगों को बरी करने के बम्बई उच्च न्यायालय के 21 जुलाई के फैसले पर गुरुवार को रोक लगाते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उस याचिका

- लेकिन हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए सभी 12 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।**

को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के फैसले को अन्य लंबित महाराष्ट्र संगठित अपराधनियंत्रण अधिनियम (मकोका) मामलों में मिसाल नहीं माना जाए। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर संबंधित सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया। पीठ ने इस

दलील पर गौर किया और स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा।

केन्द्र सरकार को संवैधानिक पदों , संस्थाओं व संविधान की परवाह नहीं- पायलट

सचिन पायलट ने टोंक में धन्ना तलाई के ड्रेनेज सिस्टम व सौन्दर्यीकरण का शिलान्यास किया



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने गुरुवार को टोंक में डेढ़ करोड़ रुपये के पानी निकासी के ड्रेनेज सिस्टम एवं सौन्दर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया।

संविधान की कोई परवाह नहीं है। करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार

अनिल अंबानी की कंपनियों पर ई.डी. ने रेड की

यह कार्यवाही अनिल अंबानी की कम्पनियों द्वारा 3000 करोड़ रु. के फर्जीवाड़े को लेकर की गई है

- आरोप है, कि अंबानी समूह की कंपनियों ने 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से प्राप्त 3000 करोड़ रु. के ऋण में भारी हैराफेरी की थी।**

प्राप्त हुई थी। ईडी को पता चला है कि अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कंपनियां सार्वजनिक धन की हेराफेरी एवं वित्तीय संस्थानों को गुमराह करने की योजना में शामिल थीं।

कहा जा रहा है कि इसमें 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से करीब 3000 करोड़ रुपयों के ऋण की कथित तौर पर हेराफेरी की गई थी। इस हेराफेरी की कड़ी में, कई मामलों में औपरचारिक मंजूरी मिलने से पहले ही ऋण वितरित कर दिया गया और बैंक में आवेदन जमा होने के दिन ही राशि भी जारी कर दी गई।

इनमें ऋण पानेवाली कुछ कंपनियों की तो वित्तीय स्थिति भी कमजोर थी और उनके पास उचित

दस्तावेजों की भी कमी थी। कहा जा रहा है कि रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लि. (आरएचएफएल) द्वारा दिए गए कॉर्पोरेट लोन में भारी उछाल देखने के बाद सेबी ने यह जानकारी ईडी के साथ साझा की थी।

ये कॉर्पोरेट लोन 2017-18 के 3,742.60 करोड़ रुपयों से बढ़ कर, 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपए हो गए थे। अब ईडी इस बात की जांच कर रही है कि कहीं ये उछाल किसी लोन डायवर्जन योजना से तो नहीं जुड़ा था।

बता दें कि ईडी की यह छापेमारी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के निराश निर्देशों के अनुसार रिलायंस कम्प्युनिकेशंस (आरकॉम) और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किए जाने के बाद शुरू हुई है।

गुरुवार को हुई ईडी की छापेमारी पर रिलायंस समूह द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि प्रमोटर की कुछ निजी कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए ऋण उन कंपनियों की योग्यता के आधार पर स्वीकृत किए गए थे।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा, भाजपा सरकार मनरेगा योजना की प्रक्रिया को इतना जटिल बना रही है कि लोग इससे जुड़ ही नहीं पायें।

के पानी की निकासी के ड्रेनेज सिस्टम एवं सौन्दर्यीकरण कार्य का शिलान्यास तथा विधायक मद से 10 लाख रुपये के राशि से वार्ड नं. 56 में बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण करते हुए कहा कि धन्ना तलाई में आज जो विकास कार्य का शिलान्यास किया है, इस कार्य के पूर्ण होने पर यहां के लोगों को गंदे पानी से निजात मिलेगी और यहां एक सुन्दर पार्क विकसित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज तथा न्यू हॉस्पिटल का कार्य शीघ्र पूर्ण होने वाला है। इससे टोंक व आसपास के लोगों को इलाज के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो विकास के कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी।

फ्री ट्रेड एग्रीमैंट के मार्फत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रोबर – अब भारतीय बाजार में आसानी से आ सकेंगे, जबकि भारतीय चाय और कई कृषि उत्पाद ब्रिटिश बाजार में अब अधिक प्रतिस्पर्धा होंगे क्योंकि टैरिफ में कटौती तुरंत प्रभाव से लागू होगी।

दोनों देशों के विकास की गति और बाजारों की बदलती मांग भविष्य में यह तय करेगी कि कौन कितना लाभ उठाएगा और कौन नहीं।

यह सोचना गलत नहीं होगा कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और बढ़ती समृद्धि के चलते भारत में लगजरी कारों की मांग बहुत तेजी से बढ़ेगी, जबकि ब्रिटेन में भारतीय चाय और कृषि उत्पादों की मांग सीमित ही रहेगी। आखिर कोई देश कारों की तरह तेजी से चाय और सब्जियां तो नहीं खरीद सकता यह बात स्पष्ट है कि भविष्य में ब्रिटेन को उन उत्पादों पर कम शुल्क का फायदा मिलेगा, जिनकी भारत में भारी मांग हो सकती है।

इसका यह मतलब नहीं है कि

भागवत ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

100 साल में इस तरह की बैठक कभी भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिस सद्भावनापूर्ण माहौल में हर मुद्दे पर चर्चा हुई और जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सबकी बातों को धैर्य से सुना, वह काबिले-तारीफ था।

उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान आरएसएस प्रमुख ने कई बातें कहीं। उन्होंने बताया कि सब इस बात पर सहमत हुए कि इस तरह की मुलाकातें हर राज्य में समय-समय पर होती रहनी चाहिए।

इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबेलो और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के इश्रेश कुमार भी शामिल हुए।

‘क्या मृत मतदाताओं को भी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्य चुनाव आयुक्त ने जोर देकर कहा कि हर मतदाते के लिए एक ज़रूरतहिन और साफ-सुथरी मतदाता सूची तैयार चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है।

उन्होंने पूछा, “क्या पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की गई एक शुद्ध मतदाता सूची, निपक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की नींव नहीं होती?” उन्होंने आगे कहा, “इन सवालों पर, कभी न कभी हम सभी को और भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर गंभीरता से सोचना होगा।”

मुख्य चुनाव आयुक्त की ये टिप्पणियाँ ऐसे समय आई हैं जब विपक्षी दल, विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल (आर.जे.डी.) और

कांग्रेस, यह आरोप लगा रहे हैं कि एस.आई.आर. प्रक्रिया के कारण 50 लाख से अधिक लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा।

कुमार ने उसी संविधान का हवाला दिया, विपक्ष के अनुसार, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से कुचला जा रहा है।

ज्ञानेश कुमार ने कहा, “भारत का संविधान ही भारत के लोकतंत्र की जननी है। चुनाव आयोग को डर है कि अगर मृत लोगों के नाम पर, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम पर, डुप्लीकेट या फर्जी और विदेशी वोटरों के नाम पर वोट डाले गए, तो चुनाव प्रक्रिया भटक सकती है। इसीलिए यह

समीक्षा बिहार में शुरू की गई है और इसे पूरे देश में ले जाया जाएगा।” उन्होंने आगे कहा। “क्या चुनाव आयोग को ऐसे मतदाताओं को सूची से नहीं हटाना चाहिए?” चुनाव आयोग द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार की मतदाता सूची से 56 लाख नाम हटाए जाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। इन 56 लाख नामों में शामिल हैं: 20 लाख मृतक मतदाता, 28 लाख अन्य राज्य में स्थायी रूप से चले गए लोग, 7 लाख ऐसे लोग जो एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं और 1 लाख ऐसे मतदाता जिनसे संपर्क नहीं हो सका। इसके अलावा, लगभग 15 लाख लोगों ने सत्यापन फॉर्म वापस नहीं किया, जिससे उनकी स्थिति भी संदेह में आ गई है।

हालांकि यह समझौता केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है। सेवाएं-जो भारत के लिए एक प्रमुख क्षेत्र हैं, भी इसका बड़ा लाभ उठाएंगी। एफटीए ने आईटी, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, वास्तुकला और परामर्श सेवाओं के लिए भारतीय कंपनियों के ब्रिटेन में प्रवेश नियमों में ढील दी गई है। वहीं, ब्रिटिश सेवा प्रदाताओं को भारत के मध्यम वर्ग द्वारा संचालित सेवा अर्थव्यवस्था तक सुनिश्चित पहुंच मिलेगी।

एक ऐतिहासिक प्रावधान एक लंबे समय से चली आ रही भारतीय चिंता को दूर करता है, यूके में कार्यरत भारतीय पेशेवरों द्वारा सामाजिक सुरक्षा भुगतान। इस समझौते के तहत, ऐसे पेशेवर अब तीन वर्षों तक इन भुगतानों से मुक्त रहेंगे, प्रत्येक कर्मचारी के लिए हजारों पाउंड की संभावित वार्षिक बचत। बदले में, भारत ब्रिटेन से आने वाले 90 प्रतिशत उत्पादों पर आयात शुल्कों का प्रस्ताव, जिससे भारतीय उपभोक्ता बाजार में प्रीमियम कारों, दवाओं, स्कॉच व्हिस्की और उच्च गुणवत्ता वाली कार्रलेट जैसे ब्रिटिश उत्पादों के लिए रास्ता खुलेगा। स्कॉच व्हिस्की और जिन जैसी ब्रिटिश वस्तुओं पर वर्तमान में 150 प्रतिशत टैक्स लगता है, जिसे तुरंत घटाकर 75 प्रतिशत और अगले दस वर्षों में 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसी तरह, ब्रिटिश लज़री कारों पर 100 प्रतिशत से अधिक आयात शुल्क लगा था, इसे घटाकर मात्रा 10 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

यह समझौता छोटे और मध्यम उद्यमों को भी सशक्त बनाता है, जिसमें सरल कस्टम प्रक्रियाएं, 48 घंटे में क्लीयरेंस और डिजिटल व्यापार सुगमता का वादा शामिल है। सीमा-पार डिजिटल व्यापार को संरक्षित किया जाएगा, जिसमें ई-कॉमर्स ड्यूटी पर रोक, ई-कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी मान्यता और सुरक्षित डेटा प्रवाह के प्रोटोकॉल शामिल हैं। हालांकि भारत खुलापन अपना रहा है, लेकिन डीज़ल वाहन, उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चे धीरे जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षण दिया गया है, यह संकेत देता है कि भारत घरेलू प्राथमिकताओं की रक्षा भी कर रहा है।

एफटीए को जुलाई में भारत की कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और इसे यूके की संसद द्वारा भी जल्द ही अनुमोदित किया जाएगा। अगले 9 से

उनका आरोप है कि मंदिर की नकल करना केदारनाथ जैसे पवित्र तीर्थस्थल की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने इसे 'सनातन धर्म' को खिलाफ एक बड़ी साजिश" करार देते हुए कहा कि यह सदियों पुराने हिमालयी मंदिर की ऐतिहासिक धार्मिक महत्ता को कमजोर करने का प्रयास है।

हालांकि यादव ने इस आलोचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन 2023 का एक पुराना वीडियो, जिसमें वे धार्मिक प्रवचनकर्ता अनिरुद्धाचार्य के साथ सड़क किनारे बातचीत करते नजर आ रहे हैं, हाल ही में वायरल हुआ है। इस वीडियो के जरिए उनकी हिंदू संतों के

साथ कथित अभद्रता की आलोचना फिर से शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त, यादव की 'सॉफ्ट हिंदुत्व' रणनीति की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्थापना से ही इसकी धर्मनिरपेक्ष पहचान रही है। भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता को अक्सर मुस्लिम तृष्टिकरण के रूप में देखा गया है-खासतौर पर उत्तर प्रदेश में।

समाजवादी पार्टी के गठन से पहले, जब सपा-संस्थापक मुलायम सिंह यादव जनता दल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1990 के अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अखिलेश यादव की वर्तमान धार्मिक मुद्रा की विश्वसनीयता को और कमजोर करती है।

भाजपा से नाराज़ हिंदू वोटों पर ...

15 महीनों में इसके लागू होने की उम्मीद है। यह समझौता केवल एक आर्थिक सुधार नहीं है, बल्कि यह एक साहसिक भू-राजनीतिक वक्तव्य है। जब वैश्विक व्यापार साझेदारियों का पुनर्गठन हो रहा है, भारत और ब्रिटेन एक-दूसरे के भविष्य पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र ने इस एफटीए का जोरदार स्वागत किया है और इसे भारत के उभरते व्यापार ढांचे में एक प्रमुख मील का पत्थर बताया है, जो वैश्विक आर्थिक एकीकरण की दिशा में बढ़ रहा है।

आरपीजी ग्रुप के वाइस चेयरमैन एक परिवर्तनकारी क्षण है। यह केवल व्यापार की जीत नहीं है, बल्कि एक आधुनिक साझेदारी का खाका है, जिसमें नवाचार, स्थिरता और समावेशी विकास को केन्द्र में रखा गया है। जैसे-जैसे भारतीय उद्योग वैश्विक होता जा रहा है, हम इस साझेदारी के अगले अध्याय में सार्थक योगदान देने की

उम्मीद करते हैं।”

फिक्की के अध्यक्ष और इमामी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन एवं एमडी, हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा, “भारत-यूके एफटीए पर हस्ताक्षर करने के व्यापार ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो वैश्विक आर्थिक एकीकरण के दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है। यह आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों का पूरक है, जिससे घरेलू उद्योग वैश्विक स्तर पर विस्तार कर सकें, प्रतिस्पर्धा बन सकें और मूल्य श्रृंखलाओं का अधिक प्रभावी तरीके से लाभ उठा सकें। फिक्की इस विकास का स्वागत करता है, जो एक अधिक लचीला और अक्सर प्रधान व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में एक कदम है, जिससे दोनों देशों और उनके नागरिकों को लाभ होगा।”

राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार को अंतर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाइन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाउस, हनुमान हट्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेरा। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय : - जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय : - जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

